संपादकीय जागरण

रविवार, 8 अप्रैल, 2018 : वैशाख कृष्ण 8 वि. 2075

प्रेम तमाम दुखों की दवा है

नेपाल से नजदीकी

नेपाल के चीन के पाले में जाने की आशंका के बीच वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए नई दिल्ली का चयन करके यही संकेत दिया कि वह भारत से संबंध सुधारने के उतने ही इच्छुक हैं जितना कि खुद भारत। यह स्थिति जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने में सहायक बननी चाहिए। अभी यह कहना कठिन है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने विवादित मुद्दों को किनारे रखकर आगे बढ़ने का जो फैसला किया उसके कितने अनुकूल परिणाम सामने आएंगे, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत और नेपाल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तौर पर जैसी निकटता है वैसे अन्य किसी देश के बीच मुश्किल से ही देखने को मिलती है। दोनों देशों के नागरिकों में एक-दूसरे के प्रति मैत्री भाव के साथ ही उनके बीच रोटी-बेटी के भी संबंध हैं। ऐसी स्थिति में उभय देशों के हित में यही है कि वे पुरानी कड़वाहट भूलकर आगे बढ़ें। एक ओर जहां भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह नेपाल की सहायता करते समय बड़े भाई की भूमिका में दिखने से बचे वहीं नेपाल को भी यह देखना होगा कि वह चीन के विस्तारवादी रवैये पर नई दिल्ली की चिंताओं को समझे। निःसंदेह नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर चीन से भी दोस्ती करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पड़ोसी देश से संबंध रखने के नाम पर उसे इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि भारतीय हितों के साथ-साथ खुद उसके हितों पर आंच आने लगे। उम्मीद है कि एक तो नेपाल का नेतृत्व खुद ही यह समझने को तैयार होगा कि चीन किस तरह छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और दूसरे, भारतीय नेतृत्व उसे यह संदेश सही तरह से देने में सफल होगा कि चीनी मदद किस तरह उसके गले का फंदा बन सकती है।

भारत के सामने चुनौती केवल नेपाल में चीन के प्रभाव को कम करने और इस पड़ोसी देश को भरोसे में लेने की ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि दक्षिण एशिया में चीन की घेरेबंदी की काट कैसे की जाए। चीन एक के बाद एक दक्षिण एशियाई देशों यानी भारत के पड़ोस में अपना दखल जिस तरह बढ़ाता जा रहा है उसे देखते हुए भारत को पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के मामले में कुछ नया करना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि मालदीव में अपनी जड़ें जमाने के बाद चीन म्यांमार में भी मदद के नाम अपना जाल फैला रहा है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी उसकी सक्रियता छिपी नहीं और यह तो जग जाहिर ही है कि पाकिस्तान स्वेच्छा से उसकी गोद में बैठने के लिए उतावला है। यह सही है कि भारत अपनी सामर्थ्य भर पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद दे रहा है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत को अन्य उपायों का सहारा लेने पर विचार करना होगा। चूंकि दक्षेस संगठन नाकाम और निष्क्रिय हो चुका है इसलिए भारत को ऐसे किसी संगठन को सक्रिय करना होगा जो नेपाल समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करे।

मिले स्थायी राहत

नगर निगम सफाई कर्मचारियों की 18 दिनों से चल रही हड़ताल का खत्म होना राहत भरी खबर है। इससे दिल्ली में चरमरा गई सफाई व्यवस्था पटरी पर आ सकेगी। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, बकाया एरियर का भुगतान करने, अस्थायी कर्मचारियों को मेडिकल कार्ड देने सहित अन्य मांगों को लेकर निगम के सफाई कर्मचारी आंदोलनरत थे। इससे उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के सभी 104 वार्डों और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी और नजफगढ़ जोन के सभी 54 वार्डों में कूड़ा उठाने और सफाई करने का काम ठप था। इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी। वहीं, निगम ने चार हजार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है जिसके बाद शनिवार सुबह से कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौट गए हैं। हालांकि कुछ कर्मचारी अब भी हड़ताल पर हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस विवाद को हल करने में इतना वक्त क्यों लगा? यदि कर्मचारियों की मांग जायज थी तो फिर उन्हें हड़ताल पर जाने की नौबत क्यों आई।

सरकार व नगर निगमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजधानी में एक दिन भी सफाई का काम न रुके

ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहली बार आंदोलन कर रहे हैं। आए दिन वे कभी वेतन न मिलने तो कभी दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं जिससे दिल्ली की सूरत बिगड़ने लगती है। हमें याद रखना चाहिए कि दिल्ली से ही प्रधानमंत्री ने अक्टूबर, 2015 में स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। इससे देश के कई शहरों की सफाई व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सूरत नहीं बदल सकी है। इस स्थिति के लिए दिल्ली सरकार, निगम व कर्मचारी सभी दोषी हैं। निगम और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्वच्छ वातावरण दिल्ली के लोगों के दें, देश की राजधानी अन्य शहरों के लिए मिसाल बन सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या शीर्ष समूह बनाने से स्मार्ट सिटी परियोजना को तेजी मिलेगी?

आज का सवाल
क्या पं. नेहरू के जन्मदिन के बजाय गुरु गोविंद सिंह बेटों की शहादत वाले दिन के मौके पर बाल दिवस मनाने की मांग सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

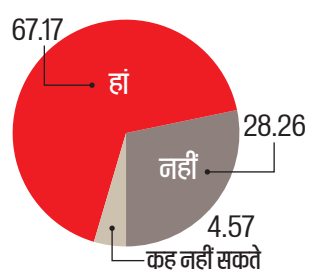

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी

संजय गुप्त

संसद को सुचारु रूप से चलाने के मामले में कोई नई परिपाटी इसलिए भी शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि संसदीय कार्यवाही का स्तर लगातार गिरता जा रहा है

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जिस तरह हंगामे, शोर-शराबे और व्यर्थ के व्यवधान की भेंट चढ़ गया उससे धन और समय की तो बर्बादी हुई ही, राजनीतिक दलों पर लोगों का भरोसा भी घटा। ऐसा होना एक तरह से भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बजना है। इससे अधिक चिंताजनक और कुछ नहीं हो सकता कि बजट सत्र में नाम मात्र का विधायी कामकाज हो सका और अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लंबित रह गए। इनमें कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन पर सरकार को अध्यादेश लाना पड़ सकता है। बजट सत्र में सरकार के विरोध के नाम पर शोर-शराबे और हंगामे की विपक्ष ने जो रणनीति बनाई उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। विपक्ष को सरकार का विरोध करने का हक है, लेकिन इसके नाम पर संसद को बंधक बनाने का अधिकार नहीं, लेकिन इसी अधिकार का जबरन इस्तेमाल किया गया। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पूरे 22 दिन तक जिस तरह अलग-अलग बहानों से संसद के दोनों सदनों को ठप कराया गया उससे साफ पता चला कि विपक्ष की रुचि सरकार को काम न करने देने की थी। राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यह सही कहा कि जो कुछ हुआ वह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं और हम सबके साथ-साथ देश की जनता ने भी बहुत कुछ खोया है।

हालांकि संसद में हंगामा पहले भी होता रहा है और पूरे के पूरे सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ते रहे हैं, लेकिन अतीत में जब भी ऐसा हुआ तब हंगामे के केंद्र में कोई एक बड़ा विषय था। उदाहरण के लिए संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक पूरा सत्र 2जी घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति की मांग के कारण हो रहे हंगामे की भेंट चढ़ गया था। चूंकि तब सत्तापक्ष संयुक्त संसदीय समिति के गठन को तैयार नहीं था इसलिए विपक्ष के लिए हंगामा करना एक विवशता सी थी। इस बार सत्तापक्ष पंजाब नेशनल बैंक घोटाले समेत विपक्ष की ओर से उठाए गए मसलों पर चर्चा को तैयार था, लेकिन विपक्षी दलों ने चर्चा से अधिक हंगामा करने में दिलचस्पी दिखाई। इसी का परिणाम यह रहा कि पहले सत्र में जहां केवल बजट पेश हुआ वहीं दूसरे सत्र में बजट से जुड़े विधेयकों के अलावा केवल एक विधेयक ही पारित हुआ। लगातार हंगामे के चलते संसद के करीब 250 कामकाजी घंटे बर्बाद हुए और इस कारण करीब 190 करोड़ रुपये व्यर्थ चले गए। यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जरूरी विधेयकों के लंबित रह जाने से देश को जो नुकसान होगा उसका आकलन करना कठिन है। विडंबना यह कि कोई भी इसकी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा में सिर्फ चार फीसद और राज्यसभा में आठ फीसद काम-काज क्यों हुआ? अगर बीता सत्र पिछले 18 साल में सबसे कम काम वाला सत्र साबित हुआ तो यह सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए, लेकिन वे ऐसे संकेत तक नहीं दे रहे हैं। उलटे जनता को सफाई देने के लिए सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं। बेहतर हो कि कोई इसकी सफाई भी दे कि संसद चली क्यों नहीं?

अवधेश राजपूत

यह अच्छा नहीं हुआ कि संसद को एक तरह से विरोध प्रदर्शन का अड्डा बना दिया गया। हैरत की बात यह है कि इस काम में कल तक राजग की सहयोगी रही तेलुगु देसम पार्टी भी शामिल रही। उसने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए न केवल सरकार और राजग से नाता तोड़ा, बल्कि अपने सांसदों के जरिये दोनों सदनों में तरह-तरह से शोर-शराबा भी किया। आंध्र की राजनीति में खुद को आगे दिखाने के फेर में तेलुगु देसम पार्टी की विरोधी वाईएसआर कांग्रेस भी हंगामा मचाने में पीछे नहीं रही। इसी तरह अन्नाद्रमुक ने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए संसद को सबसे उपयुक्त जगह माना तो अन्य दलों ने भी अपने-अपने मसले उठाकर हंगामा करने का काम किया। कांग्रेस ने पहले पीएनबी घोटाले को लेकर हंगामा किया और फिर एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया में बदलाव संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर ऐसा रुख अपना लिया मानो यह आदेश सरकार ने दिया हो। इतना ही नहीं उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में लोगों को भड़काने का भी काम किया। एक विडंबना यह भी रही कि संसद में जिन भी मसलों पर हंगामा किया गया उन्हें लेकर चर्चा करने से जानबूझकर बचा गया। अगर चर्चा हुई होती तो पक्ष-विपक्ष की राय के जरिये आम जनता इन मसलों की तह तक जा सकती थी। शायद विपक्षी दल यह चाहते ही नहीं थे कि इन मुद्दों पर नीर-क्षीर तरीके से बहस हो। इसीलिए बहस के स्थान पर हंगामे की राह पर चला गया।

हमारे राजनीतिक दल संसदीय परंपराओं को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका पता इससे भी चलता है कि बजट सत्र के दौरान ही केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तो दिया गया, लेकिन इसकी चिंता नहीं की गई कि हंगामे और शोर-शराबे के बीच इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा कैसे हो सकती है? विपक्ष को यह अच्छी तरह पता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी शुरू हो सकती है जब सदन व्यवस्थित हो, लेकिन यह जानते-बूझते हुए भी उसने सदन में हंगामा मचाना जारी रखा। शायद विपक्षी दलों ने यह तय कर लिया था कि वे ज्वलंत समस्याओं पर संसद में चर्चा नहीं होने देंगे। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि हमारे राजनीतिक दल इससे बेपरवाह हो चुके हैं कि दुनिया के अनेक देशों में भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है। यह मिसाल इसीलिए दी जाती है, क्योंकि संसद लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है।

यदि संसद में बुनियादी काम ही नहीं होंगे तो फिर यह तय है कि वही देश भारतीय लोकतंत्र का उपहास उड़ाएंगे जो उसकी मिसाल देते हैं। इसके साथ ही देश की जनता भी संसद के रवैये पर निराशा प्रकट करेगी। आज जब इसकी आवश्यकता कहीं अधिक है कि संसद अपने हिस्से का काम सही तरह करे तब यह देखना दयनीय है कि राजनीतिक दल संसद को बाधित करने पर आमादा हैं। यह सही है कि यह जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है कि संसद सही तरह चले, लेकिन विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह संसद चलने में अपना सहयोग प्रदान करे। वह ठीक इसके उलट काम कर रहा है। विपक्षी दल ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें संसद के चलने-न चलने की परवाह ही नहीं। इसे देखते हुए ऐसे तौर-तरीके बनाने की जरूरत है जिससे संसद चलाने के मामले में सत्तापक्ष के साथ ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी तय हो। संसद को सुचारु रूप से चलाने के मामले में कोई नई परिपाटी इसलिए भी शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि संसदीय कार्यवाही का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि आज के हालात में संसद चलाने के तौर-तरीकों पर नए सिरे विचार होना संभव नहीं दिखता, लेकिन राजनीतिक दलों को यह याद रखना चाहिए कि यह वह आवश्यकता है जिसकी पूर्ति होना लोकतंत्र के साथ खुद उनके अपने हित में है।

response@jagran.com

टाइगर की सजा पर दुखी हिरण

हास्य-व्यंग्य

दिन भर एक जरूरी काम में उलझा रहा। इतना कि सोशल मीडिया भी नहीं झांक सका। घर पहुंचा तो एक गिलास पानी पीकर गलती से न्यूज चैनल खोल दिया। यह क्या! यहां तो हाहाकार मचा हुआ था। भाईजान को हिरण मारने पर जेल हो गई थी। न्यूजरूम में विशेषज्ञ पानी पी नहीं रहे थे, बल्कि वह उनकी आंखों से स्वाभाविक रूप से बह रहा था। मुझे पहली बार अपने असंवेदनशील होने का अहसास हो रहा था। काश, मैंने घर आकर एक गिलास पानी न पिया होता! मैं चाहकर भी अब 'राष्ट्रीय-विलाप' का हिस्सा नहीं बन सकता था। एक और जरूरी राष्ट्रीय-कर्तव्य से मैं चूक गया था। इस 'गिल्ट' से मैं छटपटाने लगा। मुझे हल्की-सी उम्मीद सोशल मीडिया से लगी। चैनल छोड़कर वहां घुसा तो वज्रपात-सा हुआ। रुदन का स्वर वहां और तेज था। हमारे अधिकतर मित्र कई घंटे पहले भाईजान के गम में गलत हो चुके थे। वहां कोई 'स्कोप' न देखकर मैं वापस मुख्यधारा में कूद पड़ा।

एक तेज चैनल पूरी गणना के साथ चेता रहा था कि शेयर बाजार भले छह सौ अंक ऊपर चढ़ा हो पर भाई को मिली सजा से छह सौ करोड़ रुपये स्वाहा हो जाएंगे। शायद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी फैसला सुनाने वाले जज साहब को समय रहते दी गई होती तो राष्ट्र इतने बड़े संकट में न फंसता। देश को हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि चैनल के समझदार एंकर के होते हुए 'भाई' ने गलत वकील क्यों चुन लिया! वार्ता में शामिल सभी विशेषज्ञ बेहद चिंतित दिख रहे थे। ये वही जानकार थे जो नोटबंदी के नुकसान का आज तक ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा पाए थे, पर एक अभिनेता के जेल जाने पर सौ तरह के नफा-नुकसान गिना रहे थे। इनके लिए छह सौ करोड़ रुपये की रकम तो बड़ा शुरुआती आकलन था। यह चपत और बढ़ सकती है। भाईजान अगर जेल में ही पांच साल बने रहे तो कइयों का करियर हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। हिरण के लिए हम इतना नुकसान नहीं उठा सकते। वह 'टाइगर' की गोली से नहीं मरता तो भी शिकार तो वह टाइगर का ही होता! सरकार को इस पर आवश्यक दखल देना चाहिए। जरूरत पड़े तो मामले को संविधान-पीठ को भी सौंपा जा सकता है।'

संतोष त्रिवेदी

हिरण एकदम से सिसक उठा-'मैं क्यों ऐसे पुण्यात्मा की गोली के रास्ते में आ गया? मुझे यह बताना ही होगा

इतनी गंभीर तकरीर सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। ज्यादा देर यहां रुकता तो खुद के असंवेदनशील होने का अहसास लगातार दूसरी बार हो जाता। और भावुक होता, इससे पहले ही चैनल बदल लिया। यह एक सरोकारी चैनल था। इस गिरफ्तारी से निकले सरोकार बटोरने के लिए एंकर खुद नायक के आवास पर पहुंच गई थी। उसने कैमरामैन से कहा कि वह अपने कैमरे की नजर से नायक के आवास के इर्द-गिर्द छाए अंधेरे को दिखाए। जैसा कि दर्शक देख सकते हैं कि यहां कितना अंधेरा पसरा हुआ है! माफ करना, यह अंधेरा आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। आइए, हम इस काम में आपकी मदद करते हैं। यह जो घर के सामने अभिनेता के चाहने वालों की भीड़ जुटी है, सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ये जो उठे हुए हाथ आप देख रहे हैं, भले ही रोजगार से खाली हों, पर दुआओं से लबालब हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने इनकी प्रतिक्रिया ली है पर वे दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं। इस नाते 'विचलित' होने का काम हम स्वयं कर लेते हैं, परंतु आपको नहीं कर पाएंगे। कृपया यहीं हमारे साथ बने रहें।' इतने आग्रह के बावजूद मैं अपना 'विचलन' रोक नहीं पाया।

तीसरे चैनल को खोला तो वहां कुछ राहत मिली। वहां इस फैसले पर पड़ोसी देश की प्रतिक्रिया आ रही थी कि अभिनेता को उसके कर्म के लिए नहीं धर्म की वजह से सजा मिली है। सुनकर दिल को तसल्ली हुई कि दहशतगर्दी का निर्यात करने वाले देश में अभी भी हास्यबोध खत्म नहीं हुआ है और एक हम हैं जो अपने नायक को मिली सजा के लिए ढंग से अफसोस भी नहीं जाहिर कर पा रहे हैं। इस अपराध-बोध के चलते हमने तुरंत चैनल बदल दिया। इस चैनल में नायक की मानवता और उदारता के 51 किस्से बताए जा रहे थे। 'बैडबॉय' से 'भाईजान' बन जाने का रोचक सफर चल रहा था। न जाने कितनी फुस्स नायिकाओं का करियर भाईजान ने संवारा था। मुझे तो लगने लगा कि हो न हो, भाई ने इस एंकर को भी अपनी दरियादिली का सबूत दिया हो।

इस बीच न जाने कब मुझे झपकी आ गई। फिर देखा कि वही हिरण मेरे सामने खड़ा था। उसका मुझसे भी बुरा हाल था। उसे अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी। मैंने उसे सांत्वना दी। वह एकदम से सिसक उठा-'मैं क्यों ऐसे 'पुण्यात्मा' की गोली के रास्ते में आ गया? मेरी नादानी की वजह से आज सारा राष्ट्र शोक में है। हम आत्मोत्सर्ग के लिए ही पैदा होते हैं। जंगल के टाइगर से बच गए तो शहर के 'टाइगर' हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे में भाई जान कहां से दोषी हो गए! मैं स्वयं इस बात की गवाही देने जा रहा हूं।' मैं ग्लानि से भरे हिरण की गवाही का इंतजार ही कर रहा था कि खबर आ गई कि भाई जान को जमानत मिल गई।

response@jagran.com

ऊर्जा

भूल सुधार

मनुष्य से जीवन में तमाम भूलें हो जाती हैं। वास्तव में मानव से भूल होना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में व्यावहारिक होते हुए जाने-अनजाने में भूलें हो जाती हैं। कई भूलें नासमझी व अनजाने में होती हैं जबकि कई बार वह जानबूझकर गलती करता है। अनजाने में की गई भूल तो क्षमा योग्य होती है, यदि इसके लिए वह क्षमा याचना कर ले और फिर भूल न करने की प्रतिज्ञा भी करे। यदि एक गलती के पश्चात पुनः फिर वही गलती करता है और बार-बार उसी भूल को दोहराता जाता है तो इस प्रकार की भूल स्वाभाविक भूल की श्रेणी में नहीं आएगी, बल्कि यह जानबूझकर की गई गलती कहलाएगी। ऐसी भूल क्षमा योग्य नहीं होती। सर्वप्रथम यदि भूलवश कुछ गलत कार्य हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में जिसके प्रति अपराध हो गया हो उससे शीघ्र क्षमा मांग लेनी चाहिए। उसके प्रति आदर प्रकट करते हुए फिर ऐसी भूल न करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ऐसा करके वह अपने हृदय में एक विशेष प्रकार की शांति व सहजता की अनुभूति प्राप्त करेगा।

जीव को मानव देह श्रेष्ठता की ओर पग बढ़ाकर चलने के लिए प्राप्त हुआ है। श्रेष्ठ आचरण तथा श्रेष्ठ कर्मों का आश्रय लेकर उसको अपने जीवन की नौका को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वयं पर सदैव दृष्टि रखनी चाहिए। यह सत्य है कि जीव भौतिक देह से बंधा हुआ है इसीलिए उसकी समस्त चेष्टाएं वाह्य जगत की ओर होती हैं। उसकी इंद्रियां वाह्य विषयों के सेवन व चिंतन से मन को भ्रमित कर देती हैं। इसी भ्रम के वशीभूत हो जाने तथा सही निर्णय न कर पाने के कारण मनुष्य भूल कर बैठता है।

हां सिर्फ ईश्वर से भूल नहीं होती, लेकिन मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, परंतु गलती करके अकड़ दिखाकर जीव स्वयं को नीचे की ओर गिराता है। गलती करके गलती को न मानना उसके परिमाण को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे ही अपनी भूल का अहसास हो तो बिना समय गंवाए शीघ्र पश्चाताप करने का उपाय प्रारंभ कर देना चाहिए। पश्चाताप की अग्नि में तपकर स्वयं को निर्मल कर लेना चाहिए। अपनी भूल से सबक लेकर फिर गलती न दोहराने का नेक संकल्प लेते हुए अपनी आत्मा पर छाई धुंध को छिन्न-भिन्न कर देना चाहिए।

अशोक वाजपेयी

तथ्य-कथ्य

अमेरिका में रहने वाले विदेशी मूल के लोग

(आंकड़े लाख में)

स्रोत : प्यू ग्लोबल

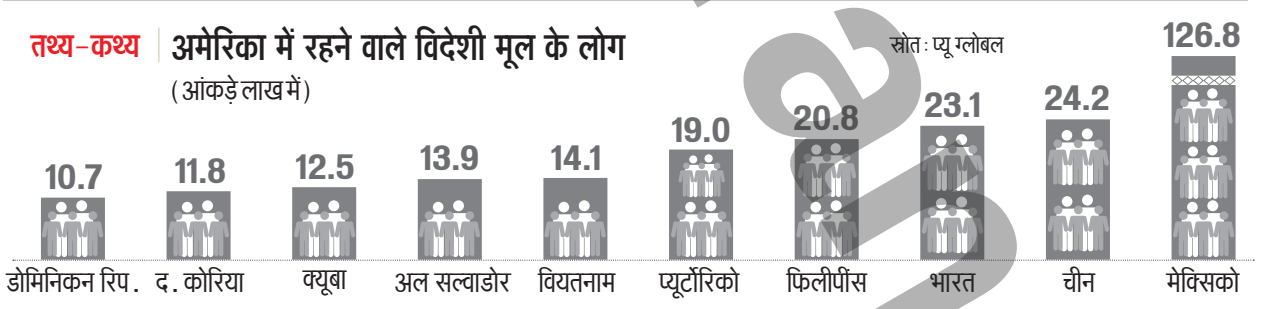

राजरंग

संसद में हंगामे की असली वजह

संसद नहीं चलने की घोषित वजह भले ही कावेरी जल विवाद, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। वहीं सत्ता के गलियारे में एक और वजह चर्चा में है, लेकिन इसके बारे में कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। और यह वजह है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जो एमसीआइ की जगह लेगा। दरअसल संसद में हंगामा करने वाले अधिकांश सांसद दक्षिण भारत के हैं और बताया जाता है कि उनमें से कई निजी मेडिकल कालेज के धंधे से जुड़े हैं। उन्हें डर है कि एक बार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनने के बाद उनके धंधे पर चोट पड़ेगी। बजट सत्र के पूरी तरह धुल जाने से इस विधेयक के पारित होने की संभावना खत्म हो गई। अब यह मानसून सत्र में ही आएगा। तब तक सभी मेडिकल कालेजों में नामांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में होगी। यानी नए आयोग का प्रभाव पड़ेगा भी तो अगले साल से और यदि लोकसभा चुनाव तक वे इस विधेयक को रोकने में सफल रहे तो नई सरकार नए सिरे से इस पर फैसला करेगी।

नौकरशाही का खेल

नौकरशाही का भी अजब खेल है। नेताओं, मंत्रियों को कितनी सूचना देनी है और किस प्रकार की देनी है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन कभी-कभी अफसरों की यह कला राजनेताओं और खासकर मंत्रियों को दुविधा में डाल देती है। ऐसी कुछ समस्या शुक्रवार को कई मंत्रालयों की वेबसाइट हैक होने की सूचना के साथ आई। केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने खुद ट्वीट कर वेबसाइट हैक होने का एलान किया, लेकिन अधिकारीगण थे कि इस सूचना की सच्चाई के बारे में लगातार अपने मंत्रियों को भ्रामक जानकारी देकर उलझा रहे थे। बताते हैं कि सही सूचना के अभाव में कुछ मंत्री तो इस संबंध में आगे क्या करना है, इसका फैसला भी नहीं कर पा रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद भ्रम की स्थिति दूर हुई और सरकार अपना पक्ष रख पाई।

महाराष्ट्र के मंत्रियों का जलवा

जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रियों के प्रदर्शन की परख करने का समाचार सामने आया है, तमाम मंत्रालयों में सक्रियता अचानक बढ़ गई है। खासकर मंत्रियों का व्यक्तिगत स्टाफ पूरे फार्म में है। मीडिया की पूछ भी बढ़ गई है, लेकिन मीडिया जिन मंत्रियों पर मोहित है वे तीनों महाराष्ट्र से हैं। सबसे आगे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का नाम है। जबकि रेलमंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग व नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु दूसरे व तीसरे नंबर पर हैं। गडकरी को इसलिए सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनकी दो सड़क परियोजनाओं का इस महीने उद्घाटन करने वाले हैं। जबकि गोयल के दो कार्यक्रमों को भी उन्होंने चुना है। प्रभु की कोई परियोजना अभी सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि पीएम विमानन मंत्रालय के किसी कार्यक्रम में भी इस महीने शिरकत कर सकते हैं। इससे अन्य मंत्रियों की बेचैनी बढ़ गई है और वे भी प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं।

नई दोस्ती के नए रंग

उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव में सपा और बसपा के अनौपचारिक गठबंधन के नतीजों से उत्साहित विपक्ष में 2019 के लिए एकजुटता की कवायद तेज हो गई है। संसद सत्र जहां हंगामे की भेंट चढ़ गया, वहीं संसद भवन का सेंट्रल हॉल तमाम विपक्षी दलों की मुलाकातों का केंद्र बना रहा। इस सबके बीच कांग्रेस के कई सांसद सेंट्रल हॉल में हो रही विपक्षी दलों की मुलाकातों पर चुटकी लेते नजर आए। एक सांसद ने मजाकिया अंदाज में कहा की शादियां स्वर्ग में और गठबंधन सेंट्रल हॉल में बनते हैं। असल में बीते हफ्ते तृणमूल नेता ममता बनर्जी और तेलुगु देसम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू दोनों ही सेंट्रल हॉल में काफी देर मौजूद रहे। साथ ही लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आगामी लोकसभा चुनावों पर बातचीत करते और तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को तलाश करते नजर आए। वहीं सेंट्रल हॉल में अखिलेश यादव की मौजूदगी को लेकर भी बसपा और सपा के कई सांसदों में उत्साह देखा गया। टीआरएस, टीडीपी, समेत बसपा के कई सांसदों को अखिलेश के साथ गर्मजोशी से बात करते देखा गया। यहां तक कि बसपा और सपा के सांसदों में भी दोस्ताना गपशप होती दिखी, लेकिन ये पूरी चर्चा कांग्रेस मुक्त नजर आई।

ट्वीट-ट्वीट

स्वास्थ्य का मतलब केवल किसी बीमारी से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह एक समग्र भाव है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत समाहित होती है।
सद्गुरु-जग्गी वासुदेव@SadhguruJV

अभी किसी को हनुमान के रेखाचित्र पर आपत्ति है तो फिर जल्द ही कोई हिंदू देवताओं में विमर्श का बिंदु भगवान शिव के रौद्र रूप पर भी केंद्रित कर सकता है कि वह तो त्रिनेत्र धारी और ब्रह्मांड के विध्वंसक हैं।
आनंद रंगनाथन@ARanganathan72

सलमान खान को जमानत मिलने के साथ ही मुझे अपनी मित्र से हुई बातचीत याद आ गई जिनका भाई एक झूठे मामले में दो साल से जेल में बंद था। गिरफ्तारी के तीन महीने बाद जब उन्होंने जमानत अर्जी लगाई थी तो जज ने उसे यह कहकर खारिज कर दिया कि अभी क्या जल्दी है, थोड़ा और रहने दो जेल में।
दीपिका भारद्वाज@DeepikaBhardwaj

अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा है कि कांग्रेस की वजह से देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ। जो लोग रोज पानी पी-पीकर कांग्रेस को कोसते हैं, उन्हें इस दिग्गज अभिनेता से कुछ सीखना चाहिए।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

जनपथ

संसद-सुप्रिम कोर्ट में हंगामे का राज,
उन्हें न आती लाज है जिनपर हमको नाज।
जिनपर हमको नाज वही करते हैं ड्रामा,
कब तक पूरा देश सहेगा ये हंगामा ?
जिन्हें न पद का भान न जानें जो अपना कद,
क्यों भेजें हम - आप उन्हें भारत की संसद !
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 263